मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- निगमायुक्त और उपायुक्त भिड़े
- भ्रष्ट मंगला का हुआ निष्कासन — 3

- मी टू : घर-घर है हैवानों की दुनिया!
- फिटनैस का मोदी गिमिक — 4

- सांप्रदायिकता की आग में राजनीतिक रोटियां सिकती हैं, गरीबों का चूल्हा नहीं — 5

- सेक्टर सात और दस बाजार में राजनीतिक फिरौतीबाजों का साया — 8

वर्ष 31 अंक -22 फ़रीदाबाद 27 मई-2 जून 2018 फोन : - 9999595632 ₹2

डिग्री की दुकान बना अवैध डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज!

आधी अधूरी फैकल्टी, क्लर्क बन बैठी प्रिंसिपल

फ़रीदाबाद (म.मो.) किसी जमाने में देश का बेहतरीन संस्थान डीएवी आज लूट, ठगी व चोरबाज़ारी का अड्डा बन कर रह गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों व कॉलेजों को चलाने वाली डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने इस शहर के एन-एच 3 नम्बर में डीएवी कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट के नाम से एक संस्थान खोल रखा है। यहां से छात्रों को एमबीए, एमसीए आदि की पेशेवर डिग्रियां दिलाई जाती हैं। इसके लिये पढाई होती है या नहीं, बढिया होती है या घटिया, इसको इसी से समझा जा सकता है कि इनके प्रोस्पेक्टस में 47 शिक्षक बताये गये हैं जबकि एमडीयू (महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी) द्वारा की गयी जांच में केवल 17 ही शिक्षक रजिस्टर में पाये गये। इनमें से भी केवल 14 ही एमडीयू द्वारा स्वीकृत पाये गये। शिक्षकों के अलावा ग़ैर शिक्षण स्टाफ़ भी यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत नहीं है।

छात्रों से ली जाने वाली फ़ीस के नाम पर भी भारी घोटाला पाया गया। एमडीयू द्वारा एमसीए की फ़ीस 36000 वार्षिक तथा एमबीए की 35000 वार्षिक निर्धारित की गयी है, जबकि कॉलेज वसूलता है 5 से 10 लाख तक, जैसी कोई आसामी फ़ंस जाय।

कॉलेज में एमडीयू तथा ऑल इन्डिया काऊंसिल फ़ॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम एक एकड़ के प्लॉट की आवश्यकता थी। इसके लिये डीएवी मेनेजिंग कमेटी ने धोखा-धड़ी करके अपने ही डीएवी सेंटिनेरी कॉलेज की 5 एकड़ ज़मीन में से एक एकड़ ज़मीन इस कॉलेज के नाम चढा दी। मजे की बात तो यह है कि भू-तल पर

प्रिंसिपल नीलम गुलाटी

इस कॉलेज का कोई दखल नहीं है, यानी भू-तल सारे का सारा सेंटेनेरी कॉलेज के पास ही है। इस कॉलेज के पास तो केवल प्रथम तल ही है।

संदर्भवश पाठक यह भी जान लें कि सेंटनेरी कॉलेज ने 5 एकड़ में से ही दो एकड़ ज़मीन डीएवी पब्लिक स्कूल के नाम कर रखी है। यानी 5 एकड़ के जिस प्लॉट पर कायदे-कानून के हिसाब से केवल एक डीएवी सेंटिनेरी कॉलेज ही खोला जा सकता था, उसी प्लॉट पर मैनेजिंग कमेटी ने धोखा-धड़ी करके व सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत खिला कर तीन संस्थान खड़े कर दिये।

सबसे गजब मामला तो है नीलम गुलाटी का जो पहले कभी इसी कॉलेज में फ़ीस क्लर्क होती थी, पिछले कई वर्षों से प्रिंसिपल की कुर्सी पर जमीं बैठी है। लेक्चरार की जिस पोस्ट पर उन्हें पहली जून 2001 में नियुक्त किया गया था, उस पोस्ट के लिये मैनेजमेंट सम्बन्धित पढाई में स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होनी चाहिये थी परन्तु नीलम गुलाटी के पास ऐसी कोई डिग्री न होने के बावजूद उसे लेक्चरार के पद पर नियुक्त कर दिया गया जबकि एमडीयू ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु हेरा-फ़ेरी एवं धोखा-धड़ी में निपुण डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने 8 सितम्बर 2009 को बतौर सहायक प्रोफ़ेसर, एमडीयू से ही स्वीकृत करा लिया। जांच कमेटी ने इस गड़बड़ झाले की पूरी जांच की सिफ़ारिश बरसों पहले की थी, लेकिन ढाक के वही तीन पात।

जो नीलम गुलाटी सहायक प्रोफ़ेसर होने की योग्यता नहीं रखती, उसे शिक्षा के ठेकेदारों (डीएवी मैनेजिंग कमेटी) ने बतौर कार्यवाहक प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा रखा है। और भी मजे की बात तो यह है कि मैडम गुलाटी जी कॉलेज में दर्शन देने के लिये सप्ताह में 2-3 बार ही, और वह भी कभी 11 बजे से पहले प्रकट नहीं होती और ढाई बजे लुप्त हो जाती हैं। क्यों न हो जब इनके पति संस्थान के सीए (चार्टरड एकाऊंटेंट) हों और मैनेजिंग कमेटी के वायस प्रेसिडेंट प्रबोध महाजन विशेष रूप से मेहरबान हों। ऐसे में पढने-पढाने से कोई ताल्लुक रखने की इस मैडम जी को जरूरत ही क्या है?

उक्त तमाम तथ्य हरियाणा विधान सभा के स्पीकर के आदेश पर 2015 में बैठाई गयी जांच कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज हैं। एमडीयू के तीन प्रोफ़ेसर-एस.एस. दहिया, के.वी.चमार तथा सतनारायण शर्मा द्वारा की गयी इस जांच की रिपोर्ट करीब ढाई वर्ष पूर्व एमडीयू के कुलपति, विधानसभा के स्पीकर तथा हरियाणा सरकार को सौंप दी गयी थी। लेकिन जिस सिस्टम को भ्रष्टाचार रूपी दीमक चट कर चुकी हो उससे कोई क्या अपेक्षा कर सकता है?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी हाल ही में इस संस्थान ने नहर पार 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है। अभी इसका सीएलयू तक हुआ नहीं और बीते सप्ताह भूमि पूजन करा कर निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी कर ली। जानकार बताते हैं कि इंडोरामा नाम की किसी कम्पनी को डीएवी वालों ने फ़ांसा है जो इस निर्माण कार्य में पैसा लगायेगी। साढे 13 करोड़ रुपये में खरीदी गयी ये ज़मीन भी किसी घोटाले से कम नहीं है।

बीके अस्पताल में एनजीओग्राफ़ी और एनजीओप्लास्टी का काला धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर की जनता को सस्ता इलाज देने के नाम पर खट्टर सरकार ने बीके अस्पताल में हृदय रोग के इलाज हेतु एक सेंटर खोला है। वास्तव में इस सेंटर की इमारत व बिजली पानी आदि तो सरकार का है बाकी सब ठेकेदार कम्पनी का है। इस धंधे को नाम दिया गया है पीपीपी मोड। कहने को तो यह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, परन्तु वास्तव में इसका परिणाम होता है पैसा पब्लिक का और प्रोफ़िट प्राइवेट का।

वैसे भी समझने वाली बात है कि जब सरकार इतने बड़े-बड़े अस्पताल खड़े कर सकती है, हजारों करोड़ खर्च करके पूरा स्वास्थ्य विभाग चला सकती है तो इस तरह के सेंटर क्यों मुनाफ़ाखोर व्यापारियों को सौंपे जाते हैं? दूसरी बात, जब सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही तो कोई प्राइवेट भला क्यों निभाने आयेगी? वह तो आयेगी केवल विशुद्ध मुनाफ़े के लिये और अधिकतम मुनाफ़ा कमाने के लिये कंपनी कुछ भी करेगी।

वह सब एक ठेकेदार कम्पनी यहां कर भी रही है। एक एनजीओग्राफ़ी करने का यहां सरकारी रेट 3500 रुपये निर्धारित है; परन्तु इन दामों पर आज तक यहां एक भी एनजीओग्राफ़ी नहीं हुई। यहां का औसतन खर्चा पड़ता है करीब 10 000 रुपये। ठगी का तरीका यह होता है कि एनजीग्राफ़ी का रेट तो 3500 ही बताया जाता है, परन्तु मरीज को एक बार अपने शिकंजे में कस लेने के बाद उसके परिजनों को डरा-डरा कर कुछ फ़ालतू के कामों की स्वीकृति ले ली जाती है। इससे कुल बिल बढ कर 8 से 10-12 हज़ार कुछ भी हो सकता है। मैट्रों जैसे बड़े व्यापारिक अस्पतालों में एनजीओग्राफ़ी का रेट ही 15000 है।

इसके बाद तमाशा शुरू होता है एनजीओप्लास्टी का। सरकार द्वारा इसका निर्धारित रेट है 48900 रुपये लेकिन किसी एक-आध मोटी सिफ़ारिश वालों को छोड़ कर किसी का भी काम इस रेट पर नहीं होता। मरीज को टेबल पर लिटाने के बाद यहां भी उसके परिजनों को डराया जाता है। उन्हें मरीज की गंभीर स्थिति एवं जान को खतरे का हवाला देकर बैलूनिंग व कई अन्य काम करने की स्वीकृति लेकर उसका बिल 90000 से एक लाख तक कुछ भी बना दिया जाता है।

भारी भरकम बिल वसूली के लिये मरीज को बताया जाता है कि उसे 5000 रुपये का एक फ़लां टीका लगाया गया, फ़िर क्लॉट निकालने के लिये अतिरिक्त बैलूनिंग की गई। इन सब कामों के नाम पर निर्धारित खर्च को बढा कर डबल कर दिया जाता है। दबाव में आया मरीज जैसे-तैसे रो-पीट कर इस बढे-चढे बिल को अदा कर लेता है।

गत सप्ताह एक ऑटो रिक्शा चालक ने रात के 12 बजे जब अपनी मां को एनजीओप्लास्टी हेतु भर्ती कराया तो उसने निर्धारित 49000 रुपये जमा करा दिये। दो तीन घंटे बाद जब काम हो गया तो कम्पनी ने 50000 रुपये और मांग लिये। ऑटो चालक भिड़ गया, अतिरिक्त पैसा देने से साफ़ मना कर दिया। झगड़ा बढा, मारपीट की नौबत आ गयी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने ऑटो चालक की बात को सही पाया और उसे बिना लुटे मां को घर ले जाने दिया।

इस तरह की लूट एवं चोर बाज़ारी तो तब है जब इस कम्पनी के पास यहां न तो कोई अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं न अन्य स्टाफ़। बस काम चलाऊ धक्का स्टार्ट स्टाफ़ के बल पर ग़रीब मरीज़ों पर हाथ साफ़ किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री रामबिलास को बधाई दीघोट गांव में 10वीं के सारे बच्चे फ़ेल

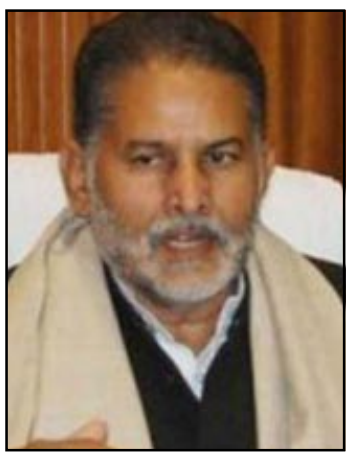

फ़रीदाबाद (म.मो.) पलवल ज़िले के गांव दीघोट स्थित रामबिलास के सरकारी स्कूल के 51 बच्चे 10 वीं की परीक्षा देने बैठे थे। इनमें से 5 नकल करते पकड़े गये तो उन पर केस बना दिया गया। शेष 46 फ़ेल हो गये। वास्तव में बेचारे नकल मारने के भी योग्य नहीं थे।

गांव के इस वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में कुल 217 छात्र-छात्रायें पढने के नाम पर पूरा वर्ष आते रहे और अपना समय बर्बाद करके जाते रहे। कारण? कारण वही कि सरकार नहीं चाहती कि ग़रीबों का कोई बालक पढ़-लिख जाय। इसलिये राज्य भर के अन्य स्कूलों की भांति यहां भी न तो कोई पढाने वाले शिक्षक तैनात किये गये और न ही शिक्षा सम्बन्धी कोई साजो-सामान स्कूल में है।

वैसे रामबिलास खुश होना चाहें तो हो सकते हैं क्योंकि इसी स्कूल में 12 वीं जमात के 23 बच्चों में से दो ने पास होकर उनकी इज्जत, अगर कोई है, को बचा लिया है। काफ़ी बड़ा गांव होने के बावजूद इस स्कूल में मात्र 18 लड़कियों समेत कुल 217 बच्चे ही पढने के नाम पर अपना समय बर्बाद करने आते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनके पास निजी महंगे स्कूलों में पढने के संसाधन नहीं हैं। साधन सम्पन्न सैंकड़ों बच्चे पलवल अथवा अन्य बढिया स्कूलों में पढने जाते हैं।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने अकेले दीघोट गांव के साथ कोई भेद-भाव करते हुए यहां के बच्चों का बेड़ा गर्क कर रखा है। हरियाणा भर के तमाम सरकारी स्कूलों की हालत कमोबेश यही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही इसी ज़िले के पृथला गांव की छात्राओं ने राजमार्ग जाम करके अपने यहां शिक्षकों की तैनाती मांगी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य भर के करीब 103 स्कूलों का 10 वीं व 12 वीं का परिणाम ज़ीरो प्रतिशत रहा है। जाहिर है इन परिणामों के फ़लस्वरूप अभिभावक भी खट्टरों व रामबिलासों की बांह मरोड़ने की अपेक्षा अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में भेजना ही बंद कर देंगे। सरकार भी यही चाहती है ताकि बच्चों की कमी का बहाना करके स्कूलों को बंद कर के अपना पिंड छुड़ाया जा सके। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी न सरकारी स्कूल रहेंगे और न इन नकटे नेताओं की नाक बार-बार कटेगी।